

7वाँ भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श

प्रलिस के लयि:

भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श, सतत वकिस लकष्य, भारत-जर्मन डजिटल वारता, उभरती डजिटल प्रौद्योगकियॉ, डजिटल कृषि, कृतरमि बुद्धमितता, इंटरनेट ऑफ थगिस (IoT), भारतीय राषटरीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS), राषटरीय धरवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR), नयु सपेस इंडिया लमितेड, नया सामूहक परमाणति लकष्य, UNFCCC COP21 पेरसि, भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगकि परषिद, भारत-मध्य पूरव-यूरोप आर्थक गलयार, प्रत्यकष वदिशी नविश (FDI), भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, नविश संरक्षण समझौता, P-75I पनडुबवी ।

मेन्स के लयि:

बदलते भू-राजनीतिक परदृश्य में भारत-जर्मनी संबंधों का महत्त्व ।

सरोत: पी.आई.बी

चर्या में क्यॉ?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और जर्मनी के संघीय चांसलर ने नई दलिली में भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श (7वें IGC) के 7वें दौर की सह-अध्यक्षता की ।

- "नवाचार, गतशीलता और स्थरिता के साथ मलिकर आगे बढना" के आदर्श वाक्य के तहत, इसने प्रौद्योगकि, नवाचार, जलवायु कार्रवाई तथा रणनीतिक सहयोग पर ध्यान केंद्रति कयि ।
- इससे पहले, जर्मनी ने भारत को एक वशिष दर्जा दयि है, जसिसे सैन्य खरीद के लयि त्वरति मंजूरी मलि सकेगी ।

भारत-जर्मनी बैठक के मुख्य बदि क्या हैं?

- जर्मनी का "भारत पर ध्यान" दस्तावेज: इसमें एक खाका प्रस्तुत कयि गया है ककिसि प्रकार भारत और जर्मनी सहयोग करके "वैश्वक कल्याण के लयि एक शक्ति" बन सकते हैं, जैसे नवाचार तथा प्रौद्योगकि नेतृत्व, सतत वकिस लकष्य आदिपर साझेदारी ।
- कुशल भारतीयों के लयि वीजा: जर्मनी ने कुशल भारतीय कार्यबल के लयि वीजा की संख्या 20,000 से बढाकर **90,000 करने का नरिणय** लयि है ।
- डजिटल और प्रौद्योगकि साझेदारी: दोनों देशों ने नवाचार को बढावा देने के लिए इंटरनेट शासन, तकनीकी वनियमन, अर्थव्यवस्था के डजिटल परिवर्तन, उभरती डजिटल प्रौद्योगकियॉ, डजिटल कृषि, कृतरमि बुद्धमितता और इंटरनेट ऑफ थगिस (IoT) के लयि एक कार्य योजना को अंतिम रूप दयि ।
- महत्त्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगकियॉ: दोनों ने महत्त्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगकियॉ, नवाचार और कौशल वकिस में नवाचार एवं प्रौद्योगकि साझेदारी रोडमैप में रेखांकति प्राथमकताओं की पुष्टि की ।
- आपदा न्यूनीकरण: आपदा न्यूनीकरण और संबंधति कषेत्रों में अनुसंधान को बढाने के लयि भारतीय राषटरीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) तथा राषटरीय धरवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताकषर कयि गए ।
- अंतरकष सहयोग: नयु सपेस इंडिया लमितेड तथा जर्मनी स्थति रमोट सेंसगि कंपनी (GAF AG) ने ओशनसैट - 3 और रीसैट - 1A (RISAT- 1A) उपग्रहों से डेटा के प्रसंस्करण के लयि जर्मनी के नयूसट्रेलटिज में अंतरराषटरीय ग्राउंड स्टेशन को अपग्रेड करने पर सहमति व्यक्त की ।
- हरति एवं सतत भवषिय: दोनों पक्षों ने नए सामूहक परमाणति लकष्य (NCQG) पर संयुक्त रूप से कार्य करने की आवश्यकता पर बल दयि, जसिमें वकिसशील देशों के लयि प्रतिवर्ष कम से कम 100 बलियन अमेरिकी डॉलर की व्यवस्था करने का आह्वान कयि गया है ।
 - दोनों पक्षों ने भारत-जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप का उद्घाटन कयि, जो भारत में सतत शहरी गतशीलता को बढावा देता है ।
- भारत-यूरोपीय संघ सामरिक साझेदारी: दोनों ने भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगकि परषिद का समर्थन कयि तथा भारत-मध्य पूरव-यूरोप आर्थक गलयार सहति कनेक्टविटी पहलों को आगे बढाने के प्रयासों का समन्वय कयि ।
- ट्रेक 1.5 संवाद: अभकिर्त्ताओं ने आपसी दृष्टिकोण की गहन समझ को बढावा देने के लयि थकि टैकों और वशिषज्ञों को शामिल करते

हुए भारत-जर्मनी ट्रेक 1.5 संवाद के महत्त्व पर बल दिया।

- **त्रिकोणीय विकास सहयोग (TDC):** अभिकर्त्ताओं ने कैमरून, घाना और मलावी में सफल पायलट परियोजनाओं को आगे बढ़ाने तथा **इथियोपिया व मेडागास्कर** में कदन्न (Millets) से संबंधित नई परियोजनाएँ शुरू करने पर सहमति व्यक्त की।
 - TDC में विकास परियोजनाओं के क्रयान्वयन के लिये **दो या दो से अधिक विकासशील देशों** के बीच साझेदारी शामिल होती है, जसिे **विकासित देश(देशों)/या बहुपक्षीय संगठन(संगठनों)** द्वारा समर्थन प्राप्त होता है।
- **पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (MLAT):** भारत और जर्मनी ने **आपराधिक मामलों में MLAT पर हस्ताक्षर किये**, जसिका उद्देश्य कानूनी मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देना है, जसिसे भारत तथा जर्मनी की **सुरक्षा चुनौतियों का संयुक्त रूप से समाधान करने की क्षमता में वृद्धि** होगी।



जर्मनी और भारत एक दूसरे के लिये क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?

- **व्यापारिक संबंध:** जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
 - वित्त वर्ष 2020-21 में द्विपक्षीय व्यापार 21.76 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो मज़बूत व्यापार संबंधों को दर्शाता है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** अप्रैल 2000 से सितंबर 2021 तक 13 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के निवेश के साथ जर्मनी भारत के लिये **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** का सातवाँ सबसे बड़ा स्रोत है।
 - चूँकि जर्मनी चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करना चाहता है, इसलिये भारत एशिया में **व्यापार संबंधों में विविधता लाने** के लिये एक प्रमुख साझेदार के रूप में सामने आ रहा है।
- **नवीन सहयोग:** जर्मन निवेश में **ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी और वनरिमाण संयंत्र** शामिल हैं, जो कनेक्टेड एवं स्वायत्त प्रौद्योगिकियों जैसे उन्नत क्षेत्रों में सहयोग पर जोर देते हैं।
 - ऐसी साझेदारियाँ भारत में **नवाचार और कौशल विकास** को बढ़ावा देती हैं।
- **बाज़ार में प्रवेश में सहायता:** **"मेक इन इंडिया मटिलसर्टैड"** कार्यक्रम जैसी पहल जर्मन SME को भारतीय बाज़ार में प्रवेश करने में सहायता करती है, जसिसे आपसी विकास को बढ़ावा मिलता है।
- **वित्तीय सहायता:** मुख्य रूप से **रियायती ऋण और तकनीकी सहायता** के माध्यम से जर्मनी की सहायता, भारत की बुनियादी अवसरचना एवं सतत् विकास पर्याप्तों को मज़बूत करती है।

- **मुक्त व्यापार समझौते:** दोनों देश **भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते** और **नविश संरक्षण समझौते** की दशा में आगे बढ़ने के लिये प्रतबद्ध हैं, जिससे व्यापार एवं नविश प्रवाह में और वृद्धि हो सकती है।
- **जर्मनी में भारतीय नविश:** जर्मनी में 213 से अधिक भारतीय कंपनियाँ मुख्य रूप से आईटी और ऑटोमोटिव क्षेत्रों में कार्य करती हैं, जो बढ़ती द्विपक्षीय आर्थिक नरिभरता को दर्शाता है।
- **साझा सुरक्षा चिंताएँ:** दोनों देश **हिंद-प्रशांत कषेत्र** में चीन द्वारा उत्पन्न खतरों को पहचानते हैं।
 - भारत सक्रिय रूप से **हथियारों के आयात पर अपनी नरिभरता कम करने** का प्रयास कर रहा है, जिसमें जर्मनी **हथियारों के सह-उत्पादन और रक्षा में नवाचार के माध्यम से सहायता कर रहा है**, जैसे कि **P-75I पनडुब्बी** का प्रस्तावित संयुक्त विकास।
- **जलवायु पर संयुक्त पहल:** साझेदारी की विशेषता **जलवायु परिवर्तन** पर सहयोग है, विशेष रूप से **हरति और सतत विकास के एजेंडे** के माध्यम से, जिसके परिणामस्वरूप हरति हाइड्रोजन और ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले कई समझौते हुए हैं।
- **जन संपर्क:** युवा शक्ति भारतीय **रोज़गार की तलाश कर रहे हैं**, जबकि जर्मनी में कुशल शर्मकों की उच्च मांग है, जिससे दोनों देशों और उनके युवाओं के लिये संभावित **'जीत-जीत'** परदृश्य उत्पन्न हो रहा है।

भारत-जर्मनी संबंधों में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **साझेदारी में गहराई का अभाव:** यद्यपि भारत और जर्मनी वर्ष 2000 से ही सामरिक साझेदार रहे हैं, लेकिन इनके बीच संबंधों को अक्सर नरिशाजनक बताया जाता रहा है।
 - **भारत-फ्रांस संबंधों** में गर्मजोशी की तुलना में भारत और जर्मनी की साझेदारी ने जुड़ाव एवं सहयोग का समान स्तर हासिल नहीं किया है।
 - **भारत और जर्मनी** के बीच एक स्वतंत्र **द्विपक्षीय नविश संधि (BIT)** की अनुपस्थिति नविशकों के विश्वास और सुरक्षा को सीमित करती है।
 - इससे गहन आर्थिक सहभागिता में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि जर्मनी नविश से संबंधित चिंताओं के समाधान के लिये भारत के साथ यूरोपीय संघ के **BTIA** पर नरिभर है।
- **लोकतांत्रिक मूल्यों पर कटाक्ष:** भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के वषिय में चिंता व्यक्त करने की जर्मनी की प्रवृत्ति ने संघर्ष उत्पन्न कर दिया है।
 - भारत में **राजनीतिक गरिफ्तारियों** पर जर्मनी की टिप्पणी जैसी घटनाओं से नई दिल्ली में नाराजगी उत्पन्न हुई।
- **रूस के प्रति मतभेद:** **यूक्रेन पर रूस के आक्रमण** की नदि करने में भारत की अनच्छिा के कारण जर्मनी में नरिशा उत्पन्न हुई है, जिसके परिणामस्वरूप एक **वशिवसनीय साझेदार** के रूप में जर्मनी के प्रति भारत की धारणा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- **सीमिति रक्षा सहयोग:** भारत के साथ रक्षा सहयोग में शामिल होने के लिये जर्मनी की **ऐतहासिक अनच्छिा**, गहन सहयोग में बाधा रही है।
- **सार्वजनिक सहभागिता और जागरूकता:** जर्मनी में भारत की तुलना में चीन के प्रति अधिक रुचि रही है, जो वरित पोषण आवंटन और मीडिया कवरेज में परलक्षित होती है।
- **पतिसत्तात्मक दृष्टिकोण:** **ग्लोबल साउथ** के संबंध में नकारात्मक भाषा वैश्विक मंच पर **भारत की स्थिति और योगदान के प्रति सराहना की कमी** को दर्शाती है।
 - इस तरह के दृष्टिकोण आपसी सम्मान और सहयोग को कमज़ोर कर सकते हैं।

आगे की राह

- **लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ावा देना:** सतत् राजनीतिक संवाद को बढ़ावा देने के लिये **नयिमति उच्च-स्तरीय बैठकों** का कार्यक्रम स्थापित करना।
 - **ट्रैक 1.5 संवाद** का वस्तितार करके इसमें व्यापारिक **अभिकर्त्ताओं, शकिषावदियों और नागरिक समाज** के प्रतिनिधियों सहित अधिक हतिधारकों को शामिल करना।
- **रक्षा संबंधों को बढ़ावा देना:** **सह-उत्पादन समझौतों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त सैन्य अभ्यासों** सहित **रक्षा सहयोग के लिये एक संरचित ढाँचा विकसित करना**।
- **संप्रभुता का सम्मान:** बाहरी आलोचना के कारण उत्पन्न टकराव को रोकने के लिये भारत के आंतरिक मामलों में उसकी **संप्रभुता** को स्वीकार करना और उसका सम्मान करना।
 - जर्मनी चर्चाओं में **अधिक सहयोगात्मक रुख** अपना सकता है तथा भारत के संदर्भ को समझते हुए उसकी चिंताओं का समाधान कर सकता है।
- **वैश्विक सहयोग:** **स्वास्थ्य, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन** जैसी वैश्विक चुनौतियों पर मलिकर कार्य करना तथा ज़मिमेदार वैश्विक शक्तियों के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करना।

?????? ???? ???? ???? :

प्रश्न: विकसित वैश्विक भू-राजनीतिक संदर्भ में भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी का मूल्यांकन कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वरित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????????

प्रश्न - व्यापक-आधारयुक्त व्यापार और नविश करार (ब्रॉड-बेस्ड ट्रेड ऐंड इन्वेस्टमेंट ऐग्रीमेंट/BTIA)' कभी-कभी समाचारों में भारत और नमिनलखिति में से कसि एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है? (2017)

- (a) यूरोपीय संघ
- (b) खाड़ी सहयोग परिषद
- (c) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
- (d) शंघाई सहयोग संगठन

उत्तर: (a)

?????

प्रश्न: "यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की दुर्घटनाओं द्वारा अफ्रीका को कृत्रिम रूप से निर्मित छोटे-छोटे राज्यों में काट दिया गया।" विश्लेषण कीजिये। (2013)

प्रश्न: कसि सीमा तक जर्मनी को दो विश्व युद्धों का कारण बनने का ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है? समालोचनात्मक चर्चा कीजिये। (2015)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/7th-india-germany-intergovernmental-consultations>

